प्रेषक,

डॉ० धीरज पाण्डेय अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांक 19 जनवरी, 2018 विषयः— हल्द्वानी के अन्तर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं सफारी की चाहरदीवारी निर्माण के आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या—1130 / 3—5 (हल्द्वानी जू) दिनांक 15.12.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हल्द्वानी के अन्तर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं सफारी की चाहरदीवारी निर्माण का उत्तराखण्ड पेयजल निगम ईकाई हल्द्वानी द्वारा गठित आगणन लागत ₹1546.41 लाख, टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण लागत ₹1384.61 लाख (₹तेरह करोड़ चौरासी लाख इकसठ हजार मात्र) पर वित्तीय वर्ष 2017—18 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹200.00 लाख (₹दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्ता एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- 1. अवमुक्त की जा रही धनराशि तत्काल कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) को उपलब्ध कराई जायेगी।
- 2. कार्य कराने से पूर्व भूवैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन कर लिया जाय।

3. कार्य की Detail design drawing अवश्य तैयार कर ली जाय।

- 4. कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
- 5. निर्माण सामग्री यथा Brick, cement, steel एवं अन्य का frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।
- 6. कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design सक्षम स्तर से Vet कराया जाय। साथ ही Reinforcement steel की मात्रा Bar bending schedule के आधार पर आंकलित की जाय तथा बचत के संबंध में वन विभाग को अवगत कराया जाय।
- 7. समस्त योजना आगणन की लागत के संबंध में कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जाय।
- 8. आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी०एस०आर० की दरें ली गयी है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियाँ भी उल्लेखित है। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मदें है। यह सही है कि यह मद डी०एस०आर० में है लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुये ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृत प्रदान करने से पूर्व उन उन मदों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

9. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति उपलब्ध होने पर तदनुसार अगली वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

10. धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—5 (लेखा नियम) भाग—1 एवं खण्ड—7 (वन लेखा नियम), आय—व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. कार्य करने से पूर्वे समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना

स्निश्चित करें।

12. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

13. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

14. कार्य एम.ओ.यू. में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम.ओ.यू. में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने में का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा तथा परियोजना कों पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

15. कार्य प्रारम्भ / धनराशि व्ययं करने से पूर्व किये जाने से पूर्व यदि आवश्यक हो तो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927

के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय।

उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या—27 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 02—पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन, 110—वन्य जीवन परीरक्षण, 02—हल्द्वानी में जू निर्माण, 24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0—S1801270225 दिनांक 15.01.2018 संलग्न है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या—142 / XXVII(4)/2017 दिनांक 12.01.2018 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 धीरज पाण्डेय) अपर सचिव

## संख्या-112 / X-2-2018-12(104)2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।

2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।

3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड निगम, हल्द्वानी (नैनीताल)

5. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।

7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, संचिवालय, देहरादून।

सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

10. गार्ड फाईल।

उप सचिव

## बजट आवंटन वितीय वर्ष - 20172018

## Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 112/X-2-2018-12(104)2016

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1801270225

आवंटन पत्र दिनांक -15-Jan-2018

## **HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)**

: लेखा शीर्षक

4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

02 - हल्द्वानी में जू निर्माण (2406-01-800-48 से स्थानान्तरित

00 - 0

Vote			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	2000000	20000000
None and the second	0	20000000	20000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

20000000

